

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा
अपर सचिव न्याय एवं उपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-१

देहरादून, दिनांक 07 जनवरी, 2008

विषय:- अपर महाधिवक्ता को अनुमन्य फीस में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 126-एक(6)/छत्तीस(1)/न्या. अनु./2005 दिनांक 12 सितम्बर, 2005 एवं अपर महाधिवक्ता को अनुमन्य फीस का स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश संख्या 241/XXXVI/ (1)/2006 दिनांक 13 जुलाई, 2006 को अधिकमित करते हुए श्री राज्यपाल मा० उच्चतम न्यायालय, दिल्ली हेतु आवद्ध किये जाने वाले अपर महाधिवक्ता को लक्ताल प्रभाव से निम्नलिखित दरों पर फीस दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) रिटेनर फीस नियत	— रु० 15,000 प्रतिमाह (रुपये पन्द्रह हजार मात्र प्रति माह)
(2) पुस्तकालय भत्ता	— रु० 1,500 प्रतिमाह (रुपये एक हजार पाँच सौ मात्र प्रतिमाह)
(3) मा० उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमन्य फीस (चाहे एक से अधिक कितने मामलों में बहस की जाये)	— रु० 10,000 प्रति कार्य दिवस (रुपये दस हजार प्रतिकार्य दिवस)

2— इस सम्बन्ध में होने वाला क्या आय-व्यय अनुदान संख्या 04 के अधीन लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-आयोग-उत्तर-114-विधि सलाहकार परामर्शदाता

(काउंसिल)–00–03–महाधिवक्ता–00–16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा ।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अंशात्मकीय संख्या 1200/वित्त अनुभाग–5/2008 दिनांक 07 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव, न्याय

संख्या: 07(1)/XXXVI/ (एक)2008तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओवराग मध्य, माजरा, देहरादून ।
- 2— कोषाधिकारी देहरादून ।
- 3— श्री अरुणेन्द्र चौहान, विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
- 4— सुश्री रचना श्रीवास्तव, अपर महाधिवक्ता (उत्तराखण्ड), 139 न्यू लायर्स चैम्बर्स, मगवानदास रोड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
- 5— इस्ला बैंक अनुभाग ।
- 6— वित्त अनुभाग–5 ।
- 7— निदेशक एन.आई.सी. उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 8— विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,


(के० पी० पाटनी)
अनुसचिव ।